



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 13 जुलाई, 1998/22 आषाढ़, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 27th May, 1998

No. HFW-B (A) 2-7/96.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to set up "State Illness Assistance Fund" for financing long-term and expensive specialised medical treatment needed by the poor in the State. This Fund will provide assistance to the poor for whom expensive but essential treatment is out of reach under the existing health system. The Fund will be administered by the Indian Red Cross Society, Himachal Pradesh Branch, as per scheme prepared by the Himachal Pradesh Health Department (Annexure-A).

By order,
C. P. SUJAYA,
ACS-cum-Secretary. (H. & F. W).

जरूरतमन्द गरीबों को लम्बी बीमारी की अवस्था में कीमती व विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु योजना

भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मन्त्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के माध्यम से गरीब लोगों को लम्बी बीमारी की अवस्था में कीमती विशेषज्ञता सेवाएं प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण स्कीम की घोषणा की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर "राज्य बीमारी सहायता निधि" के रूप में एक कोष स्थापित करने का प्रावधान है।

1. निधि के स्रोत :

(1) राज्य सरकार द्वारा कोष के लिए दी गई अनुदान राशि का 50 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।

(2) सामान्य लोगों/संगठनों/संस्थानों से दान/चन्द।—सामान्य लोगों/संगठनों/संस्थानों द्वारा कोष के लिए दी गई राशि/दान आयकर अधिनियम की धारा 89-जी के अन्तर्गत कर से मुक्त होगी।

2. पात्रता

इस निधि को गरीब लोगों को लम्बी बीमारी तथा कीमती विशेषज्ञता चिकित्सा उपचार हेतु सहायता के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।

"गरीब" का तात्पर्य उन लोगों से है जो योजना आयोग द्वारा दी गई परिभाषा "ग्रामीण गरीब" और "शहरी गरीब" के अनुसार तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं।

निधि को अस्पताल स्तर पर सुविधाओं के उत्थान के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और इसका प्रयोग केवल "गरीब" मरीजों के चिकित्सा उपचार के लिए सहायता के रूप में किया जाएगा।

3. निधि का प्रचालन :

इस निधि का प्रचालन इंडियन रेडक्रास सोसाईटी की हिमाचल प्रदेश शाखा, जो पंजीयन सहकारी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत एक दानवीर (चैरीटबल) संस्था के रूप में पंजीकृत है, द्वारा किया जाएगा।

इस निधि का प्रचालन निम्न वृहत् दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा

(I) अनुदान प्राप्ति एवम् जिलों में निधि का आवंटन

कोष के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि और राज्य सरकार की अनुदान राशि या व्यक्ति विशेष/एजेंसी से प्राप्त दान राशि को सोसायटी के अलग बैंक खाते में रखा जाएगा जिसका सदुपयोग महालखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण की शर्त पर किया जाएगा। इस निधि को किसी अन्य स्कीम/कोष से नहीं जोड़ा जाएगा।

भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि तथा राज्य सरकार का अंशदान भारत सरकार/राज्य सरकार के वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी अनुदेशों की शर्तों के अन्तर्गत होगा।

निधि का जिलावार आवंटन सामान्यतः पहचान किए गये गरीब लोगों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

भारत/राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई राशि व इसके उपयोग वारे रिपोर्ट राज्य रैंड क्रॉस सोसायटी शाखा द्वारा प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

(II) निधि के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान की विधि .

स्कीम का समूचे प्रदेश में जिला रैंड क्रॉस समितियों/उपमण्डल स्तर की समितियों/महिला मण्डलों/युवक मण्डलों/पंचायतों/सहकारी समितियों और ऐसे अन्य स्वैच्छिक संगठनों जो सहयोग के लिए आगे आ सकें, के माध्यम से प्रचार किया जाएगा।

स्कीम के प्रचार हेतु लोक सम्पर्क, ग्रामीण/शहरी विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के पैरा मैडीकल स्टाफ की मदद ली जा सकती है।

ऐसे पात्र व्यक्ति जो अस्पतालों में धनाभाव के कारण अपना उपचार करवाने में असमर्थ है, को उक्त स्कीम के व्यापक प्रचार से सहायता हेतु आगे आने में मदद मिलेगी।

ऐसे पात्र व्यक्तियों, जो गरीबी के कारण अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते को ऐसी वित्तीय सहायता जिसमें रोगी का यातायात व्यय भी शामिल है, रैंड क्रॉस सोसायटी और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दी जा सकती है। सहायता के लिए पात्र रोगी जो अस्पतालों में दाखिल हैं, की पहचान उनकी देख-रेख से सम्बन्धित डाक्टर/पैरा मैडिकल स्टाफ द्वारा की जाएगी।

(III) पात्र मामलों के प्रार्थना-पत्रों की स्वीकृति/परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया

पहचान किये गये समस्त व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्रों का मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर पर निम्न मापदण्डों के आधार पर परीक्षण किया जाएगा:—

- (i) कि प्रार्थी मरीज के पाम योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार क्रमशः “ग्रामीण गरीब” और “शहरी गरीब” के अनुरूप गरीब होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। “ग्रामीण गरीब” के मामले में यह प्रमाण-पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा तथा “शहरी गरीब” के मामले में सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के सचिव/कार्यकारी अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने चाहिए।
- (ii) कि रोगी की बीमारी ऐसी है जिसमें महंगी दवाईयां/आप्रेषन/परीक्षण इत्यादि शामिल हैं, जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सामान्य बजट में उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थना पत्रों की जांच उपरान्त अधिकारी उन पर अपनी सिफारिश करेगा तथा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्र पर वांछित वित्तीय सहायता अंकित करेगा। तत्पश्चात सभी प्रार्थना पत्र जिला रैंड क्रॉस कार्यकारी समितियों की स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे।

(IV) अस्पतालों को सहायता स्वीकृत करने व निधि रिलीज करने की प्रक्रिया:

जैसा कि ऊपर कहा गया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सिफारिश किए गये मामले जिला रैंड क्रॉस शाखा की कार्यकारी समितियों द्वारा पूरी जांच उपरान्त 20,000/- रुपये तक (प्रति मामला) स्वीकृत कर दिये जाएंगे 20,000/- रुपये से अधिक राशि के मामले सम्बन्धित जिला रैंड क्रॉस कार्यकारी समिति द्वारा राज्य रैंड क्रॉस कार्यकारी समिति को भेजे जाएंगे, जो ऐसे मामले स्वीकृत करने में सक्षम होंगे।

व्यक्तिगत मामलों में स्वीकृत की गई राशि सम्बन्धित अस्पताल को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी जाएगी। अस्पताल प्रशासन तदनुसार पात्र गरीब मरीजों का आवश्यक उपचार करवा कर इस सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला रैड-क्राफ्ट कार्यकारी समितियों को भेजेगा जो इसकी संकलित विवरणी राज्य रैडक्राफ्ट शाखा को भेजेगा। ये विवरणियां जिला शाखा द्वारा त्रैमासिक आधार पर भेजी जाएगी।

प्रत्येक जिला रैड क्रॉस सोसायटी द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की एक सूची प्रत्येक 6 मास उपरान्त अग्रणी समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित की जाएगी जिसमें उनकी बीमारी के ब्योरे सहित स्वीकृत धनराशि का विवरण दिया जाएगा।

4. गरीब लोगों के उपचार हेतु अस्पतालों की पहचान की प्रक्रिया :

इस निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन्हीं पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध करवाई जाएगी जो राज्य सरकार के अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के अस्पतालों में अपना उपचार करवाएंगे। एस अस्पतालों की सूची प्रत्येक जिला अस्पतालों को उपलब्ध करवाई जाएगी और आम जनता की सूचनार्थ व्यापक स्तर पर प्रकाशित भी की जाएगी।

SCHEME REGARDING ILLNESS ASSISTANCE FOR FINANCING LONG-TERM AND EXPENSIVE SPECIALISED MEDICAL TREATMENT NEEDED BY THE POOR

OBJECTIVES OF THE SCHEME

The Government of India through the Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health, has announced an important scheme for providing financial assistance to the poor people in cases of long term and expensive specialised medical treatment needed by them. This scheme provides for establishment of a fund named as "State Illness Assistance Fund" at the State level.

1. Sources of Fund :

(i) Against the contribution of the State Government the Government of India would contribute towards this fund to the extent of 50% of such contributions.

(ii) Donations from the General Public/Organisations/Institutions :

The contributions made by General public/institutions towards the State fund would be eligible for tax exemption under Section 80-G of Income Tax Act.

2. Eligibility :

The Fund is to be utilised for financing long term and expensive specialised medical treatment needed by the poor.

The "poor" means the persons belonging to families below the poverty line as per Planning Commission definition of 'Rural Poor' and 'Urban Poor' and as revised from time to time.

The fund would not be used for upgrading the facilities at the hospital level and would be used only as assistance for medical treatment of the "Poor" patients.

3. Operation of fund :

The fund shall be operated upon through the Indian Red Cross Society, Himachal Pradesh Branch which is a charitable institution registered under the Registration of Societies Act, 1860.

For operation of the Fund, the following broad guidelines will be kept in view :

3(i) Receipt of grant and allocation of funds to the districts :

The grant received from Government of India and contributions made by the State Government or donations received from individual donors/agencies towards this fund will be kept in a separate bank account of the Society and its utilisation shall be subject to the audit by the Auditor General. This fund shall not be mixed with any other scheme/fund.

The release of fund by the Government of India and contribution of the State will be subject to the conditions enumerated in the financial rules of the Government of India/State Government and instructions framed from time to time.

District-wise allocation will be made generally on the basis of the number of identified poor people.

The report in respect of funds released by the Government of India/State and utilisation thereof will be sent to the State Government by the State Red Cross Branch by 31st December every year.

3(ii) Procedure for identifying the eligible persons to be given assistance under this fund :

Wide publicity to this scheme will be given throughout the State through the District Red Cross Committees, Sub-Divisional level Committees, Mahila Mandals, Yuvak Mandals, Panchayats, Co-operative Societies and such other voluntary organisations as may come forward to cooperate in this regard.

The help of Public Relations Department, Rural/Urban Development Department and paramedical staff of medical department can be sought.

Wide publicity is expected to help eligible individuals to come forward to admit themselves in hospitals for treatment which otherwise they might have avoided on account of their inability to afford.

The persons who are otherwise eligible, if not in a position to reach the hospitals on account of their poverty could be given financial help through Red Cross and other voluntary organisations in terms of transportation charges etc. The eligible persons admitted in the hospitals would be identified for help by the doctors/para-medical staff attending upon such patients.

3 (iii) Procedure for accepting/screening applications of deserving cases :

All the applications of the eligible persons thus identified will be examined at the level of Chief Medical Officers broadly on the basis of following parameters :—

- (i) That the applicant patient possesses a certificate to the effect that he is a poor person as per Planning Commission definition of rural and urban poor, respectively. In case of Rural poor such a certificate should be issued by the Block Development Officers concerned

and in case of urban poor the certificate should be issued by the Secretary/Executive Officers of concerned Urban local Bodies.

(ii) That the illness of the patient is such as requires treatment through costly medicines/operation/tests etc. which are otherwise not available from the general budget of the State Government in the Health Department. After screening the applications will endorse his recommendations thereon spelling out the required financial help for each individual application. All applications will be sent to the District Red Cross Executive Committees for sanction.

3 (iv) Procedure for sanctioning of assistance and release of funds to the hospitals :

The cases recommended by the concerned Chief Medical Officers as mentioned above shall be sanctioned after thorough scrutiny by the District Red Cross Branch Executive Committees to the extent of Rs. 20,000/- per case. The cases where more than Rs. 20,000/- are to be sanctioned the same shall be sent by the concerned District Red Cross Executive Committees to the State Red Cross Executive Committee which shall have the powers of sanction in such cases.

The funds thus sanctioned in individual cases shall be released to the concerned hospital through Bank draft. The hospital authorities will provide necessary treatment to the eligible poor patients and give the utilisation certificate to the District Red Cross Executive Committees which will send a compiled statement of utilisation of funds to the State Red Cross Branch. These statements shall be sent by the District Branch, Committees on quarterly basis.

Every District Red Cross Society will publish a list of beneficiaries alongwith amount sanctioned indicating therein the illness for which the funds were sanctioned in a leading newspapers every six months for the information of the general public.

4. The Machinery of Identification of Hospitals for Treatment of the Poor :

The financial assistance from this fund shall be permissible only to those eligible persons who undergo treatment in State Government hospitals and hospitals recognised as such by the State Government in the private sector for reimbursement of cost of treatment. The list of such Hospitals will be made available to all the districts hospitals and will also be widely published for information of general public.